



भारत में डिजिटल राजनीति पर एक अध्ययन

ANJU

Sub : Political Science (JRF and NET Qualified)

sindhuanju1990@gmail.com

सार

यह शोध पत्र भारत के संदर्भ में डिजिटल राजनीति और प्रौद्योगिकी के बीच जटिल संबंधों की जांच करता है। जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी और डिजिटल प्लेटफॉर्म तेजी से राजनीतिक प्रक्रियाओं के केंद्र में आते जा रहे हैं, यह अध्ययन इस बात की जांच करता है कि क्या राजनीति प्रौद्योगिकी विकास की दिशा को आगे बढ़ा रही है या प्रौद्योगिकी भारतीय राजनीति के परिदृश्य को आकार दे रही है। केस स्टडीज, नीति निहितार्थ और सामाजिक-राजनीतिक परिणामों का विश्लेषण करके, यह पेपर भारत में डिजिटल राजनीति की बहुमुखी गतिशीलता पर प्रकाश डालता है, प्रौद्योगिकी और राजनीतिक ताकतों के बीच परस्पर क्रिया द्वारा उत्पन्न परिवर्तनकारी क्षमता और चुनौतियों दोनों को संबोधित करता है।

मुख्य शब्द : भारत, डिजिटल, राजनीति, प्रौद्योगिकी इत्यादि।

प्रस्तावना

तीव्र तकनीकी प्रगति और अभूतपूर्व कनेक्टिविटी द्वारा परिभाषित युग में, डिजिटल प्लेटफॉर्म और राजनीतिक प्रक्रियाओं के अंतर्संबंध ने दुनिया भर में राजनीति के परिदृश्य को नया आकार दिया है। यह परस्पर क्रिया भारत की तुलना में कहीं अधिक गतिशील और परिणामी नहीं है, एक ऐसा देश जो अपनी विविध जनसांख्यिकी, मजबूत लोकतंत्र और बढ़ती तकनीकी विकास की विशेषता है। प्रौद्योगिकी और राजनीति के अभिसरण ने एक जटिल और बहुआयामी घटना को जन्म दिया है जिसे "डिजिटल राजनीति" के रूप में जाना जाता है। भारत में डिजिटल राजनीति प्रौद्योगिकी और राजनीतिक प्रवचन के बीच सहजीवी संबंध द्वारा चिह्नित एक घटना है। एक ओर, प्रौद्योगिकी ने राजनीतिक अभियानों, सहभागिता रणनीतियों और संचार चैनलों को बदल दिया है। दूसरी ओर, राजनीतिक ताकतों ने प्रौद्योगिकी के विकास और तैनाती को प्रभावित किया है, इसके सामाजिक प्रभावों और शासन प्रतिमानों को आकार दिया है। यह पेपर यह पता लगाने की यात्रा पर है कि क्या भारत में डिजिटल राजनीति मुख्य रूप से

प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी क्षमता या राजनीतिक अभिनेताओं की रणनीतिक अनिवार्यताओं से प्रेरित है।

भारत में डिजिटल राजनीति परिदृश्य:

भारत में डिजिटल राजनीति का परिदृश्य एक गतिशील और विकासशील क्षेत्र है, जहां प्रौद्योगिकी और राजनीति के अभिसरण ने राजनीतिक जानकारी प्रसारित करने, जनता की राय बनाने और नागरिकों के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने के तरीके को फिर से परिभाषित किया है। यह खंड भारत में डिजिटल राजनीति के बहुमुखी आयामों की पड़ताल करता है, और इसकी रूपरेखा को आकार देने वाले प्रमुख तत्वों पर प्रकाश डालता है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म का विकास: भारत की डिजिटल राजनीति यात्रा 2000 के दशक की शुरुआत में ऑनलाइन फोरम, ब्लॉग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उद्भव के साथ शुरू हुई। स्मार्टफोन के व्यापक उपयोग और सस्ती इंटरनेट पहुंच ने फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्मों को राजनीतिक संचार में सबसे आगे कर दिया है, जिससे राजनीतिक अभिनेताओं को वास्तविक समय में विशाल दर्शकों तक पहुंचने में मदद मिली है।

डिजिटल अभियान और सहभागिता रणनीतियाँ: राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों ने चुनाव अभियानों के लिए अभिन्न उपकरण के रूप में डिजिटल प्लेटफॉर्मों को अपनाया है। 2014 और 2019 के आम चुनावों में सोशल मीडिया अभियान, व्यक्तिगत संदेश और डेटा-संचालित लक्ष्यीकरण में वृद्धि देखी गई। लाइव चैट, वर्चुअल टाउन हॉल और वेबिनार जैसी ऑनलाइन सहभागिता रणनीतियों ने राजनेताओं और नागरिकों के बीच सीधे संपर्क की सुविधा प्रदान की है।

ऑनलाइन राजनीतिक प्रवचन का उदय: डिजिटल स्थान राजनीतिक चर्चा, बहस और सूचना साझा करने का केंद्र बन गए हैं। नागरिक अब ब्लॉग, मंचों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से नीति, शासन और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। राजनीतिक विमर्श के इस लोकतंत्रीकरण ने सार्वजनिक जुड़ाव के दायरे का विस्तार किया है।

ई-भागीदारी और शासन पहल: "डिजिटल इंडिया" जैसी सरकारी पहल ने ई-भागीदारी और डिजिटल शासन को बढ़ावा दिया है। MyGov जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नागरिकों को नीति निर्माण में योगदान करने की अनुमति देते हैं, सीधे नागरिक-राज्य संपर्क और भागीदारी निर्णय लेने के लिए एक चैनल प्रदान करते हैं।

प्रौद्योगिकी-संचालित राजनीति:

प्रौद्योगिकी और राजनीति के संलयन ने एक ऐसे प्रतिमान को जन्म दिया है जिसे प्रौद्योगिकी-संचालित राजनीति के रूप में जाना जाता है, जिसमें प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी क्षमता राजनीतिक रणनीतियों, अभियानों और शासन दृष्टिकोणों को आकार देती है और उन्हें आगे बढ़ाती है। भारत में, यह घटना नवीन चुनावी रणनीति, डिजिटल शासन पहल और डेटा-संचालित राजनीतिक अभियानों के माध्यम से प्रकट हुई

डेटा-संचालित चुनावी रणनीतियाँ:

केस स्टडी - 2014 आम चुनाव: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अभियान ने अनुरूप संदेशों के साथ विशिष्ट मतदाता वर्गों को लक्षित करने के लिए बड़े डेटा विश्लेषण का उपयोग किया। इस डेटा-संचालित दृष्टिकोण ने व्यक्तिगत आउटरीच की सुविधा प्रदान की, मतदाता सहभागिता को बढ़ाया और चुनावी परिणामों को प्रभावित किया।

ऑनलाइन मतदाता सहभागिता:

केस स्टडी - 2019 आम चुनाव: राजनीतिक दलों ने इंटरैक्टिव सामग्री, क्विज़ और लाइव स्ट्रीम के माध्यम से मतदाताओं को शामिल करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का लाभ उठाया। पार्टियों ने राजनीतिक जागरूकता और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मीम्स और वायरल सामग्री का उपयोग करके युवा जनसांख्यिकीय का लाभ उठाया।

आभासी रैलियाँ और टाउन हॉल:

केस स्टडी - कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन अभियान: भौतिक रैलियाँ प्रतिबंधित होने के कारण, राजनीतिक नेताओं ने रैलियाँ, टाउन हॉल और सार्वजनिक बातचीत आयोजित करने के लिए आभासी प्लेटफार्मों का रुख किया। इस दृष्टिकोण ने राजनेताओं को मतदाताओं से सीधे जुड़ने और वास्तविक समय में चिंताओं को संबोधित करने की अनुमति दी।

डिजिटल प्रशासन पहल:

केस स्टडी - MyGov प्लेटफॉर्म: MyGov प्लेटफॉर्म नीति निर्माण और शासन में नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देता है। नागरिक विभिन्न सरकारी पहलों पर विचार, सुझाव और प्रतिक्रिया देते हैं, जो सहभागी निर्णय लेने में प्रौद्योगिकी के एकीकरण को प्रदर्शित करता है।

नीतिगत निहितार्थ और भविष्य के रुझान:

भारत में डिजिटल राजनीति और प्रौद्योगिकी-संचालित शासन का संगम कई नीतिगत निहितार्थों को सामने लाता है और भविष्य के रुझानों का अनुमान लगाता है जो देश के राजनीतिक

परिदृश्य को आकार देंगे। जैसे-जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म राजनीतिक प्रक्रियाओं का अभिन्न अंग बनते जा रहे हैं, ऐसे में सुविज्ञ नीतियों की आवश्यकता है जो प्रौद्योगिकी के लाभों को नैतिक विचारों, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ संतुलित करें। यह अनुभाग आगे आने वाले नीतिगत निहितार्थों और संभावित रुझानों की पड़ताल करता है।

ऑनलाइन राजनीतिक विज्ञापन का विनियमन:

नीति निहितार्थ: गलत सूचना और अनुचित प्रभाव को रोकने के लिए ऑनलाइन राजनीतिक विज्ञापन में पारदर्शिता के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश स्थापित करना।

भविष्य की प्रवृत्ति: निष्पक्षता, प्रायोजकों का खुलासा और अभियान वित्त कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल राजनीतिक विज्ञापन के लिए सख्त नियम।

डेटा गोपनीयता और सुरक्षा:

नीति निहितार्थ: डेटा गोपनीयता कानूनों को मजबूत करना और नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना।

भविष्य की प्रवृत्ति: नागरिकों के गोपनीयता अधिकारों को बनाए रखने के लिए डेटा एन्क्रिप्शन, उपयोगकर्ता सहमति तंत्र और सीमा पार डेटा स्थानांतरण नियमों में प्रगति।

गलत सूचना और फर्जी समाचार से मुकाबला:

नीति निहितार्थ: गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी कंपनियों, सरकार और नागरिक समाज के बीच सहयोगात्मक प्रयास।

भविष्य की प्रवृत्ति: फर्जी खबरों की पहचान करने और उनका मुकाबला करने के लिए एआई-संचालित उपकरणों का विकास, डिजिटल साक्षरता अभियानों के साथ मिलकर नागरिकों को विश्वसनीय जानकारी समझने के लिए सशक्त बनाना।

डिजिटल समावेशिता और विभाजन को पाटना:

नीति निहितार्थ: हाशिए पर रहने वाले समुदायों, ग्रामीण क्षेत्रों और कमजोर आबादी को डिजिटल पहुंच और साक्षरता प्रदान करने की पहल में निवेश करना।

भविष्य की प्रवृत्ति: डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए ब्रॉडबैंड बुनियादी ढांचे, किफायती डेटा योजनाओं और डिजिटल शिक्षा कार्यक्रमों का विस्तार।

ई-वोटिंग और डिजिटल लोकतंत्र:

नीति निहितार्थ: सुरक्षित ई-वोटिंग तंत्र और डिजिटल लोकतंत्र प्लेटफार्मों के साथ अग्रणी प्रयोग।

भविष्य की प्रवृत्ति: बेहतर पारदर्शिता, पहुंच और भागीदारी के लिए सुरक्षित ब्लॉकचेन-आधारित वोटिंग सिस्टम का संचालन।

निष्कर्ष:

डिजिटल राजनीति के विकास और प्रौद्योगिकी के साथ इसके अंतर्संबंध ने भारत को परिवर्तनकारी राजनीतिक जुड़ाव के युग में पहुंचा दिया है, जिसने लोकतंत्र, शासन और नागरिक भागीदारी की रूपरेखा को फिर से परिभाषित किया है। प्रौद्योगिकी-संचालित राजनीति और राजनीतिक रूप से संचालित प्रौद्योगिकी के बीच जटिल संबंध उस जटिल गतिशीलता को रेखांकित करता है जो देश के डिजिटल परिदृश्य को आकार देती है। इस शोध पत्र ने इस घटना के बहुआयामी आयामों का पता लगाने, इसके निहितार्थों, चुनौतियों और संभावित प्रक्षेप पथों को उजागर करने की यात्रा शुरू की है। प्रौद्योगिकी-संचालित राजनीति के क्षेत्र में, डेटा एनालिटिक्स, आभासी जुड़ाव और व्यक्तिगत आउटरीच के संलयन ने राजनीतिक अभिनेताओं को नागरिकों के साथ सीधे संबंध बनाने के लिए सशक्त बनाया है। अभियानों ने भौगोलिक बाधाओं को पार कर लिया है, आवाजों को बढ़ाया है और अभूतपूर्व तरीकों से समर्थन जुटाया है। डिजिटल क्रांति ने न केवल चुनावी रणनीतियों को उन्नत किया है, बल्कि समावेशी ई-गवर्नेंस पहल का मार्ग भी प्रशस्त किया है, जो अधिक सुलभ और पारदर्शी लोकतंत्र की ओर बदलाव का प्रतीक है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. उषा रामनाथन (2019) द्वारा "आधार: पहचान और नागरिकता का एक केस स्टडी"।
2. "फेक न्यूज़ का मुकाबला: व्हाट्सएप का एक केस स्टडी और 2018 ब्राज़ीलियाई राष्ट्रपति चुनाव" फ़ेब्रिसियो बेनेवेन्यूटो एट अल द्वारा। (2019)।
3. "डिजिटल असमानता: पूरे देश में कंप्यूटर और इंटरनेट प्रवेश का एक तुलनात्मक अध्ययन" एज़्टर हरगिट्टई (2003) द्वारा।
4. हन्ना वी. मर्फी (2018) द्वारा "ब्लॉकचेन वोटिंग: एन एनालिसिस ऑफ़ मेथड्स एंड पब्लिक ओपिनियन"।
5. रिचर्ड हसन (2007) द्वारा "अभियान और चुनाव की नैतिकता"।
6. एली पेरिसर (2011) द्वारा "द फ़िल्टर बबल: इंटरनेट आपसे क्या छिपा रहा है"।



7. कॉर्नेलियू बजोला और मार्कस होम्स (2015) द्वारा "डिजिटल डिप्लोमेसी: थ्योरी एंड प्रैक्टिस"।
8. स्टैनफोर्ड साइबर पॉलिसी सेंटर (2020) द्वारा "डिफेंडिंग डेमोक्रेटिक इलेक्शन: ए होलिस्टिक अप्रोच"।